



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225]

No. 225]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 18, 1974/वैशाख 28, 1896
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 1974/VAISAKHA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 18th May 1974

S.O. 298(E).—Whereas the industrial undertaking known as The Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, is engaged in the Scheduled Industry namely, Aluminium Industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri J. Morwaha, Senior Industrial Adviser, Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), Government of India, New Delhi.

Members

2. Shri D. K. Chakravorty, Deputy Adviser, Finance, Bureau of Public Enterprises, New Delhi.
3. Shri A. Bose, Secretary, Department of Closed and Sick Industries, Government of West Bengal.

The above body shall submit its report to the Central Government within a period of 15 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 4/6/74-CI

D. K. SAXENA, Jt. S

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई 1974

का० आ० 298 (अ).—यतः दि ऐल्यूमिनियम कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् ऐल्यूमिनियम उद्योग में लगा हुआ है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अनुसूचित उद्योग और लोक हित में आवश्यक रीति से किया जा रहा है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामले की परिस्थितियों में, पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है :—

1. श्री जे० मरवाह, ज्येष्ठ औद्योगिक सलाहकार, इस्पात और खान मंत्रालय, (खान विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली—अध्यक्ष
2. श्री डी० के० चक्रवर्ती, उप सलाहकार, वित्त, लोक उद्यम ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य
3. श्री ए० बोस, सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार—सदस्य

उपरोक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेगा ।

[सं० एफ० 4/6/74—सी यू सी]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।